परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार एवं विकास हेतु भिलाई में स्थापित किया गया है।	651	भिलाई नगर निगम को मंगल भवन के मासिक किराये का भुगतान किया जाता है।	
2	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	एस.टी.पी.आई. के साथ एन.आई.टी रायपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	20000	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप एवं स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम में योगदान हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई.) की स्थापना	
3	मुख्यमंत्री ई-समीक्षा	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	31000	1. सीएम डैशबोर्ड राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने में मदद । 2. सीएम सचिवालय में एक केंद्रीकृत निगरानी उपकरण 3. सीएम सचिवालय स्तर पर पहलों की निगरानी और मूल्यांकन में सहायता	
4	बिल्डनेक्स्ट परियोजना	शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों का वेबसाईट का डिजाईन, संचालन एवं एप्लीकेशन निर्माण करना तथा इसके लिये इन-हाऊस मैनपावर की भर्ती किया जाना	28000	विभिन्न विभागों की सेवाओं, मुख्यमंत्री फ्लैगशीप योजनाओं, लोक सेवा गारंटी आदि योजनाओं के लिए पोर्टल एवं एप्स बनाने हेतु	
5	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	230000	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	
6	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	28800	1. नए सिस्टम इंटीग्रेटर का निविदा के द्वारा चयन 2. परियोजना के वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ निकास प्रबंधन (एक्जीट मैनेजमेंट) का कार्य 3. नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा डिजीटल सचिवालय 2.0 का निर्माण एवं क्रियान्वयन	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	60000	संचालन एवं रखरखाव, हार्डवेयर एवं सर्वर लाइसेंस के लिए, एस.एम.एस. सेवा, मानव संसाधन, नए एस.आई. का भुगतान (ऑनबोर्ड करने के लिए), नई सेवाओं और अन्य विविध आवश्यकताओं की जानकारी के लिए	
8	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	272200	1. एसडीसी 1.0 का रखरखाव और एसडीसी 2.0 के समानांतर ट्रांजिशन 2. प्रस्तावित राज्य डाटा केंद्र के ऑन-प्राइमरी क्लाउड की तैयारी 3. मौजूदा एसडीसी अनुप्रयोगों के नए बिल्ड ऑन-प्राइम क्लाउड में माइग्रेशन 4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में डिजास्टर रिकवरी की तैयारी 5. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में डिजास्टर रिकवरी में आवेदन का माइग्रेशन 6. नव निर्मित डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट का परीक्षण	
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	नेशनल ई-गवर्नेंस आशिक्षण - शासकीय सेवकों को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित आशिक्षण देना	2000	छत्तीसगढ़ आशासन अकादमी में आशिक्षण कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाना एवं प्रत्येक कमरे में कम्प्यूटर नेटर्वकिंग एवं कम्प्यूटर लैब स्थापना हेतु।	
10	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना	ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाना	28800	विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
11	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना	21730	एक सशक्त इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर की स्थापना	
12	छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स परियोजना	राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक सूचनाओं को केन्द्रीयकृत कर विभागों को प्रबंधन कार्य हेतु जिओ इन्फॉर्मेटिक्स/जीआईएस एवं रिमोट सेंसिग आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य के शासकीय विभागों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।	1000	ऑनलाईन जिओ पोर्टल एवं मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कर विभागों से संबंधित भौगोलिक सूचनाओं को अद्यतित कर सूचनाओं को उपलब्ध कराना।	
13	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेंस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	19638	28 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन करना	
15	स्टेट पोर्टल परियोजना	शासन के नवीन पोर्टल का रोलआउट एवं कियान्वयन करना	2800	राज्य के समस्त विभागों का वेबसाईट का अपडेशन एवं रखरखाव	
16	छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	स्थापना मद अंतर्गत कार्यालयीन व्यय आदि का रखरखाव एवं संधारण	115000	चिप्स हेतु स्थायी कार्यालय की स्थापना, जो स्मार्ट सिटी के आई.टी की आवश्यकता में महत्वपूर्ण है।	
17	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	4500	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	
18	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	110000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	
19	मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष भवनों में वाई-फाई सुविधा की स्थापना	मंत्रालय भवन और विभागाध्यक्ष भवन में वाई-फाई इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव हेतु	25000	लगभग 2000 उपयोगकर्ता द्वारा एक साथ वाई-फाई के द्वारा 1 जीबीपीएस डाटा उपयोग किया जा सकता है।	
20	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	विश्व बैंक की सहायता से पब्लिक वित्त के प्रबंधन में अकाउन्टीबिलीटी में सुधार, राजस्व	200000		

परिणामी बजट वर्ष 2021–22

विभाग– इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष– सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021–22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		प्रशासन को मजबूत करना एवं चयनित योजनाओं के लाभ हेतु वितरण की दक्षता में सुधार करना।		योजना के अंतर्गत एकीकृत सक्रिय ई-शासन प्रणाली प्रदान करना।	
21	संचार क्रांति योजना	राज्य में मोबाईल नेटवर्क का विस्तार एवं मोबाईल के उपयोग को बढ़ावा देना	1000000	मोबाइल वितरण और सेवाओं के लिए कॉन्ट्रेक्टर का भुगतान	
22	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	150000	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	